















# विदेश संदेश

## काठमाडू में सरकारी शिक्षकों की हड्डताल से ट्रैफिक व्यवस्था चरमार्ह

काठमाडू। नेपाल के सरकारी शिक्षकों की हड्डताल आज तीसरे दिन में प्रवेश कर गई हजारों शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन के कारण काठमाडू में यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। अब तक सरकार के साथ वार्ता के सभी प्रयास फिल रहे हैं। नेपाल शिक्षक महासंघ के



आहान पर देशभर के शिक्षक नेपाल की संसद में पेश किए गए नए शिक्षा विधेयक के विरोध में सड़कों पर हैं। यह शिक्षक सुवह से शाम तक काठमाडू के मार्हीपर मडला से संसद भवन तक प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षक महासंघ की अध्यक्ष कमला तुलाधर ने बताया कि सरकार से तीन चरणों में वार्ता हुई पर कोई नोटों नहीं निकल पाया है। आज फिर वार्ता होनी है। महासंघ ने सरकारी शिक्षकों और विद्यालय को स्थानीय निकाय के मातहत रखने का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि 17 मार्गों रखी गई हैं। अधिकांश मार्गों संविधान संसोधन से जुड़ी हैं। इसलिए तकाल इनको पूरा नहीं किया जा सकता। सरकार की तरफ से वार्ता का नेतृत्व कर उप प्रधानमंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ ने कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज वार्ता के बाद हड्डताल खत्म होने की उम्मीद है।

## अमेरिकी एनएसए सुलिवन बोले: भारत रूस नहीं है, चीन के पास अपनी चुनौतियां; हमारी प्राथमिकता राष्ट्रीय सुरक्षा

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा मलाहकार (एनएसए) जेक सुलिवन का बयान सामने आया है, जिसमें उनसे जब पछ गया कि आखिर क्यों अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारत और चीन को पास दिया जा रहा है और रूस को आर्थिक सहायता दी जा रही है? इसपर उन्होंने बताया कि हमने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरों से बचाने के लिए कई तरह की कार्रवाई की है उन्होंने कहा कि भारत रूस नहीं है, और चीन की अपनी चुनौतियां हैं, जिनसे हम अपने संदर्भ में निपत्ते हैं। इसलिए, निश्चित रूप से, हम एक-एक करके देशों से जैसे कैसे निपत्ते हैं, जिसके चलते मरमें हो जाएंगे।



अमेरिका ने किया कनाडा का समर्थन गैरताल है कि खालिकानी आंतकी हाईप्री फिल निजर की हत्या के मामले में अमेरिका ने एक बार फिर भारत पर लगाए आरोपों की जांच में कनाडा का समर्थन करने की बात कही है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि किंतु भी देश को इस तरह की 'विशेष छूट' नहीं मिल सकती। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम के लिए किसी भी देश को विशेष छूट नहीं मिल सकती। हम इसके खिलाफ खड़े हैं और अपने बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा करेंगे। हम कनाडा के साथ भी लगातार परामर्श लेंगे क्योंकि वह कानूनी और राजनीतिक प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं।

## नीरव मोदी को लंदन में निजी तौर संचालित जेल में स्थानांतरित किया गया

लंदन। भारत में बांधित और भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को ब्रिटेन की सबसे बड़ी और सबसे भीड़भाड़ वाली जेलों में से एक से लंदन में एक निजी तौर पर संचालित जेल में स्थानांतरित किया गया है। नीरव भारत में धोखाधड़ी और धन शोषण के मामलों में बांधित है। ब्रह्मपुत्रावार को यह जानकारी मिली। नीरव (52) को असफल प्रत्यवर्षण अपेल कार्यालयी के संबंध में लंदन में उच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए 150,247.00 पाउंड के जुमाने के संबंध में मजिस्ट्रेट की अदालत में सुनवाई के लिए पेश होना था। हालांकि, सामने को अंतिम क्षण में नवंबर तक के लिए स्थगित करना पड़ा क्योंकि पूर्वी लंदन में बार्किंगसाइड मजिस्ट्रेट अदालत में नीरव को तकनीकी कारणों से बीड़ियों लिंक से पेश नहीं किया जा सका। अदालत के एक अधिकारी ने कहा, 'उसे आंतरिक स्थानांतरण के तहत एचएमपी (हिज मैजेस्ट्री प्रिज़ज) वैइसवर्थ से एचएमपी टेम्पसाइड में स्थानांतरित कर दिया गया था, जिसके बारे में अदालत को आज तक जानकारी नहीं थी।' दरअसल, वैइसवर्थ जेल से एक सदिंदग आतकावादी फरार हो गया था जिसके बाद उसकी तलाशी के लिए अधिकारी शुरू किया गया था।

## कनाडा-भारत राजनीतिक विवाद : पीएम जस्टिन ट्रूडो ने फिर आरोपों को गंभीरता से लेने की अपील की

टोरंटो। कनाडा के प्रधानमंत्री व्यवस्था के लिए खड़े हैं।

जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि



कारण हैं कि कनाडा की धरती पर एक कनाडा के नागरिक की हत्या

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक स्वामी श्री योगी सत्यम फॉर योग संस्कृत समिति द्वारा विएन इंटरप्राइजेज 1/6C मालव कुंज कट्टरा प्रयागराज से मुद्रित एवं क्रियोग आश्रम एंड अनुसंधान संस्थान झूंझी, प्रयागराज उत्तर प्रदेश से प्रकाशित।

सम्पादक स्वामी श्री योगी सत्यम् RNI No: UPHIN/2001/09025

आपिस नं.: 9565333000 Email:- akhandaibharatsandesh@gmail.com

सभी विवादों का व्याय क्षेत्र प्रयागराज होगा।

## भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान ने संयुक्त राष्ट्र को वैश्विक समरस्याओं के निवारण में बताया अक्षम

### संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने की मांग

न्यूयार्क। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के समूह जी-4 ने संयुक्त राष्ट्र संघ को वैश्विक समरस्याओं के निवारण में अक्षम करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा से अलग हुई इन चारों देशों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने की मांग

न्यूयार्क। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के समूह जी-4 ने संयुक्त राष्ट्र संघ को वैश्विक समरस्याओं के निवारण में अक्षम करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा से अलग हुई इन चारों देशों की बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी व अस्थायी सदस्यों को बढ़ाने की मांग

एलग भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के समूह जी-4 की ऐसा होना चाहिए जो समकालीन भू-राजनीतिक व्यवस्थाओं का

की विदेश मंत्री योको कमिकावा और भारत के विदेश मामलों के सचिव संजय वर्मा शामिल हुए।

बैठक में कहा गया कि जटिल सकटों के कारण बहुपक्षवाद पर काफी दबाव है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक समरस्याओं का प्रभावी और समय से निवारण में अक्षम साबित हो रहा है, ऐसे में इसमें सुधार की जरूरत है।

बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त प्रेस वक्तव्य में कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी और गैर-स्थायी दोनों श्रियों में विस्तार की जरूरत है।

जिससे इसे ज्यादा प्रभावी, वैध और कुशल बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में शामिल चारों देशों ने संयुक्त राष्ट्र से इस अहम मुद्दे पर आगे बढ़ने की उम्मीद की।

बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विदेश मंत्री मात्तो विएरा, जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक, जापान

के विदेश मंत्री योको कमिकावा और भारत के विदेश मामलों के सचिव संजय वर्मा शामिल हुए।

प्रचण्ड ने विश्व समुदाय को अपील की।

देश के भीतर और बाहर भी समझदारी विकसित करने का प्रयास किया जा रहा। उन्होंने विश्व समुदाय से इसमें मदद करने की अपील की।

प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने कहा कि शांति प्रक्रिया से संबंधित सच्च विधेयक संसद संसद में पेश किया जा चुका है। उन्होंने विश्व समुदाय को इस बात के लिए अश्वस्त किया कि गम्भीर आपाराधिक मामलों के दोषियों को आम अपील नहीं दी जाएगी।

बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक, जापान

के विदेश मंत्री योको कमिकावा और भारत के विदेश मामलों के सचिव संजय वर्मा शामिल हुए।

बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक, जापान

के विदेश मंत्री योको कमिकावा और भारत के विदेश मामलों के सचिव संजय वर्मा शामिल हुए।

प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने कहा कि शांति प्रक्रिया से संबंधित सच्च विधेयक संसद संसद में पेश किया जा चुका है। उन्होंने विश्व समुदाय को इस बात के लिए अश्वस्त किया कि गम्भीर आपाराधिक मामलों के दोषियों को आम अपील नहीं दी जाएगी।

बैठक के बाद जारी किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक, जापान

के विदेश मंत्री योको कमिकावा और भारत के विदेश मामलों के सचिव संजय वर्मा शामिल हुए।

प्रधानमंत्री प्रचण्ड ने कहा कि शांति प्रक्रिया से संबंधित सच्च विधेयक संसद संसद में पेश किया जा चुका है। उन्होंने विश्व समुदाय को इस बात के लिए अश्वस्त किया कि गम्भीर आपाराधिक मामलों के दोषियों को आम अपील नहीं दी जाएगी।

बैठक के बाद जारी किए